

बिजनौर जनपद में सामाजिक-आर्थिक अवस्थापनात्मक तत्वों के परिवर्तित स्वरूप का अध्ययन

¹डा० रश्मि शर्मा रावल; ²नरेश कुमार

¹शोध पर्यवेक्षक, विभागाध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, आर० एस० एम०(पी०जी०)कॉलेज, धामपुर, बिजनौर(उ०प्र०)

²शोधार्थी, भूगोल विभाग, आर० एस० एम०(पी०जी०)कॉलेज, धामपुर, बिजनौर(उ०प्र०)

ARTICLE DETAILS

Article History

Published Online: 15April2019

Keywords

सामाजिक, आर्थिक, अवस्थापनात्मक तत्व।

ABSTRACT

किसी प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अनिर्वाय एवं आधारभूत तत्व की परिस्थितया; एवं व्यवस्थाएँ अवस्थापना तत्व कहलाते हैं। अवस्थापनात्मक तत्वों के अर्न्तगत किसी प्रदेश या स्थान विशेष की उन्नति के निर्धारण हेतु आधारभूत सुविधाएँ, साधन सेवाएँ, सरकारी एवं प्रशासनिक क्षेत्र की सेवाओं को भी सम्मिलित किया गया है। किसी भी क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्था तथा उसके विकास प्रक्रिया की गति सामान्यतः उन्हीं तत्वों पर आधारित होती है। प्रस्तुत शोध पत्र में बिजनौर जनपद में सामाजिक-आर्थिक अवस्थापनात्मक तत्वों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य के सन्दर्भ में अध्ययन किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक अवस्थापनात्मक तत्वों के अर्न्तगत शिक्षण संस्थाएँ, परिवहन सेवाएँ, वित्तीय संस्थाएँ एवं विपणन केन्द्रों का अध्ययन किया गया है। जनपद में सामाजिक-आर्थिक अवस्थापनात्मक तत्वों का आकलन करने के लिए इन तत्वों में हुए परिवर्तन को आधार बनाया गया है। जिसकी गणना हेतु जिला सांख्यिकीय पत्रिका वर्ष 1995, 2005 तथा 2015 का उपयोग किया गया है। अवस्थापनात्मक तत्वों के अर्न्तगत शिक्षण संस्थाएँ, परिवहन सेवाएँ, वित्तीय संस्थाएँ एवं विपणन केन्द्रों में हुए परिवर्तन का परिकलन सम्पूर्ण जनपद स्तर पर किया गया है। सामाजिक-आर्थिक अवस्थापनात्मक तत्वों के द्वारा किसी क्षेत्र के प्राकृतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं में मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन करके इसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है।

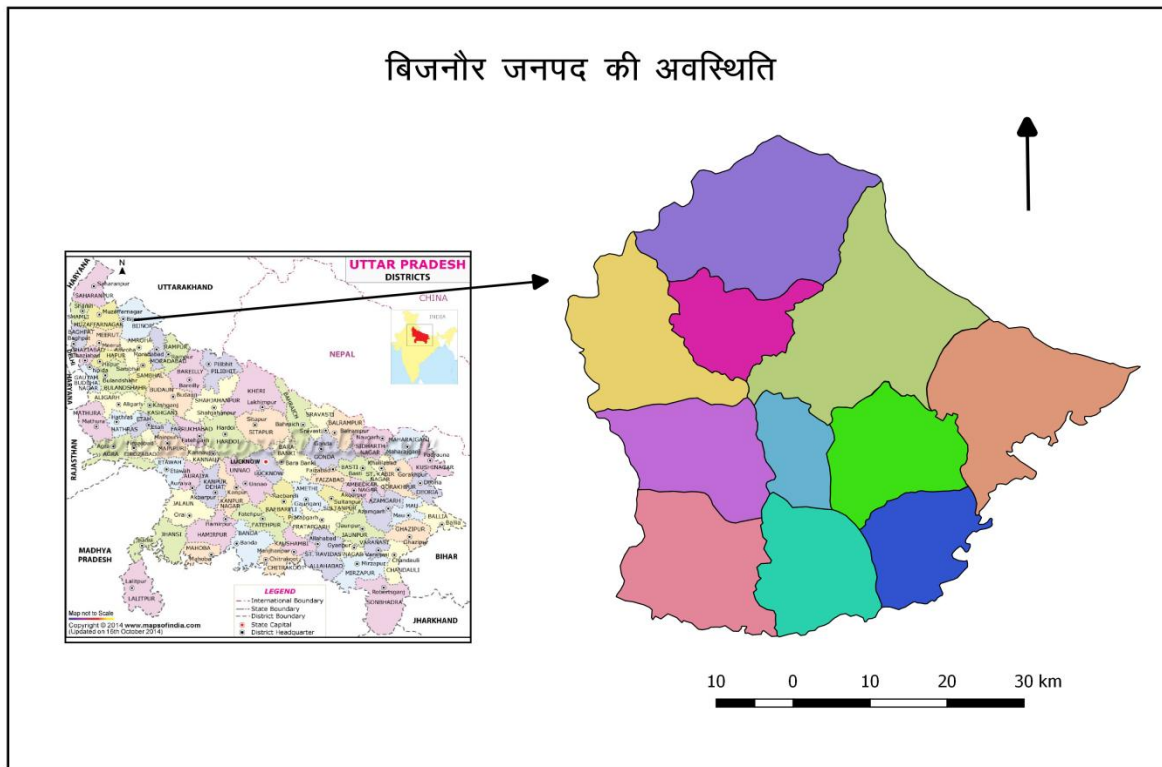
प्रस्तावना:-

बिजनौर जनपद के सामाजिक-आर्थिक विकास के अर्न्तगत उन सेवाओं एवं सुविधाओं को सम्मिलित किया जाता है, जो अर्थव्यवस्था के सम्पूर्ण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। अध्ययन क्षेत्र के लिए आवश्यक सेवाओं को अवस्थापनात्मक तत्वों की संज्ञा दी जाती है। इन तत्वों के समुचित उपयोग से न केवल क्षेत्र का आर्थिक स्वरूप बल्कि सामाजिक व राजनितिक विकास भी संभव है। अवस्थापनात्मक तत्वों की सर्वसुलभता किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है १९९२-९३ किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तथा वर्तमान विकास का भूवैज्ञानिक प्रतिरूप सामान्य रूप से अवस्थापनात्मक तत्वों पर आधारित होता है। इन तत्वों के अभाव में प्राथमिक एवं गैर प्राथमिक सामाजिक-आर्थिक क्रियाएं सुचारु रूप से संचालित नहीं हो सकती हैं। क्योंकि इसके अर्न्तगत उन सभी तत्वों को सम्मिलित किया जाता है, जो किसी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय:-

बिजनौर जनपद उत्तरप्रदेश राज्य के उत्तर-पश्चिम भाग में स्थित है। प्रशासनिक दृष्टि से यह जनपद मुरादाबाद मण्डल का अंग है। इसका विस्तार 29°2' उ० अक्षांश से 29°58' उ० अक्षांश तथा 78° पूर्वी देशान्तर से 78°59' पूर्वी देशान्तर के मध्य एवं भौगोलिक क्षेत्रफल 4561 वर्ग कि०मी० है। जनपद का आकार त्रिभुज के समान है। उत्तर-दक्षिण इसकी अधिकतम लम्बाई 100 कि० मी० तथा पूर्व-पश्चिम चौड़ाई 90 कि०मी० है। जनपद की उत्तरी सीमा उत्तराखण्ड राज्य से लगी हुई है तथा इसके दक्षिण में मुरादाबाद और अमरोहा, पश्चिम में मेरठ और मुज्जफरनगर तथा पूरब में उधमसिंह जनपद स्थित है। जनपद में कुल 11 विकासखण्ड, 26 नगर तथा 2186 ग्राम हैं।

मानचित्र संख्या 1 बिजनौर जनपद का अवस्थिति मानचित्र

**विधि तंत्र:-**

प्रस्तुत अध्ययन जिला सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद बिजनौर, कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, बिजनौर, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान उत्तर-प्रदेश द्वारा प्राप्त द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक अवस्थापनात्मक तत्वों का अध्ययन करने के लिए जनपद के सभी विकासखण्डों में शिक्षण संस्थाएँ, परिवहन सेवाएँ, वित्तीय संस्थाएँ एवं विपणन केन्द्रों से सम्बन्धित आंकड़ों का उपयोग किया गया है। चूंकि बिजनौर जनपद एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। इसलिए यहाँ के सामाजिक-आर्थिक विकास पर उपलब्ध अवस्थापनात्मक तत्वों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जनपद स्तर पर

शिक्षण संस्थाएँ, परिवहन सेवाएँ, वित्तीय संस्थाएँ एवं विपणन केन्द्रों में हुए परिवर्तन का आकलन वर्ष 1995, 2005 और 2015 के आधार पर किया गया है।

शिक्षण संस्थाएँ:-

किसी भी देश अथवा प्रदेश की प्रगति शिक्षा द्वारा ही संभव है। क्योंकि शिक्षा सामाजिक-आर्थिक एवं राजनैतिक विकास प्रक्रिया में सहायक होती है। किसी भी क्षेत्र का विकास वहा; के शैक्षिक स्तर पर ही निर्भर होता है। बिजनौर जनपद में वर्ष 1995 से 2015 के मध्य शिक्षण संस्थाओं में हुए परिवर्तन को तालिका संख्या 1 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या 1: बिजनौर जनपद की शिक्षण संस्थाएँ (वर्ष 1995-2015)

शिक्षण संस्थाएँ	1995	2005	2015
प्राथमिक विद्यालय	1439	2699	3664
उच्च प्राथमिक विद्यालय	58	95	11
माध्यमिक विद्यालय	16	42	61
महाविद्यालय	0	2	7
स्नातकोत्तर विद्यालय	0	0	2
औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र	0	3	18

स्रोत:- जिला सांख्यिकीय पत्रिका (वर्ष 1995, 2005 तथा 2015), अर्थ एवं संख्या विभाग, बिजनौर।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 1995 में बिजनौर जनपद के अर्न्तगत 1439 प्राथमिक विद्यालय जो वर्ष 2005 में बढ़कर 2699 तथा वर्ष 2015 में 3664 हो गयी। वर्ष

1995 में उच्च प्राथमिक विद्यालय की संख्या 58 थी जो वर्ष 2005 में बढ़कर 95 हो गयी। परन्तु वर्ष 2015 में उच्च प्राथमिक विद्यालय की संख्या में कमी आयी और यह घटकर

11 हो गया। इसी प्रकार जनपद में वर्ष 1995 में माध्यमिक विद्यालय की संख्या 16 थी जो वर्ष 2005 में बढ़कर 42 तथा वर्ष 2015 में 61 हो गयी। वर्ष 1995 में अध्ययन क्षेत्र में महाविद्यालय, स्नातकोत्तर विद्यालय तथा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की संख्या 0 थी। परन्तु वर्ष 2005 में जनपद के अर्न्तगत महाविद्यालय तथा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की संख्या में वृद्धि हुई और इसी के साथ महाविद्यालय की संख्या 2 तथा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की संख्या 3 हो गयी। वर्ष 2015 में बिजनौर जनपद में महाविद्यालय, स्नातकोत्तर विद्यालय तथा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या क्रमशः बढ़कर 7,2 तथा 18 हो गयी।

परिवहन सेवाएँ:-

वर्तमान समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुचने के लिए परिवहन अति आवश्यक तत्व है। परिवहन साधनों के द्वारा कम समय तथा कम लागत में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। किसी क्षेत्र की प्रगति में सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक एवं राजनैतिक विकास उन्नत परिवहन व्यवस्था पर ही निर्भर करता है। बिजनौर जनपद में वर्ष 1995 से 2015 के मध्य परिवहन साधनों को तालिका संख्या 2 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या 1: बिजनौर जनपद की परिवहन सेवाएँ (वर्ष 1995-2015)

परिवहन के साधन	1995	2005	2015
सड़को की लम्बाई	2272	3001	4930
रेलवे स्टेशन(संख्या)	27	24	24
बस स्टेशन(संख्या)	204	217	145

स्रोत:- जिला सांख्यिकीय पत्रिका (वर्ष 1995, 2005 तथा 2015), अर्थ एवं संख्या विभाग, बिजनौर।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 1995 में बिजनौर जनपद के अर्न्तगत सड़को की लम्बाई 2272 कि०मी० थी जो वर्ष 2005 में बढ़कर 3001 कि०मी० तथा वर्ष 2015 में 4930 कि०मी० हो गयी। वर्ष 1995 में अध्ययन क्षेत्र में रेलवे स्टेशन की संख्या 27 थी। परन्तु वर्ष 2005 तथा 2015 में रेलवे स्टेशन की संख्या में कमी आयी और यह घटकर 24 हो गयी। इसी प्रकार जनपद में वर्ष 1995 में बस स्टेशन की संख्या 204 थी जो वर्ष 2005 में बढ़कर 217 हो गयी। परन्तु वर्ष 2015 में बस स्टेशन की संख्या घटकर 145 ही रह गयी।

वित्तीय संस्थाएँ:-

किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए वित्तीय संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वर्तमान समय में वित्तीय संस्थाओं की रूचि ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि वयवस्था, पशुपालन तथा कुटीर उद्योगों में है। वित्तीय संस्थाओं के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यपद्धति में परिवर्तन करना सरल हो जाता है। बिजनौर जनपद में वर्ष 1995 से 2015 के मध्य वित्तीय संस्थाओं को तालिका संख्या 3 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या 1: बिजनौर जनपद की वित्तीय संस्थाएँ (वर्ष 1995-2015)

वित्तीय संस्थाएँ	1995	2005	2015
राष्ट्रीयकृत बैंक	88	96	157
गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक	46	53	75
ग्रामीण बैंक	34	39	49

स्रोत:- जिला सांख्यिकीय पत्रिका (वर्ष 1995, 2005 तथा 2015), अर्थ एवं संख्या विभाग, बिजनौर।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 1995 में बिजनौर जनपद के अर्न्तगत राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या 88 थी जो वर्ष 2005 में बढ़कर 96 तथा वर्ष 2015 में 157 हो गयी। वर्ष 1995 में अध्ययन क्षेत्र में गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या 46 थी। वर्ष 2005 तथा 2015 में गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या में वृद्धि हुई और यह बढ़कर 53 तथा 75 हो गयी। इसी प्रकार जनपद में वर्ष 1995 में ग्रामीण बैंक की संख्या 34 थी जो वर्ष 2005 में बढ़कर 39 तथा 2015 में ग्रामीण बैंक की संख्या 49 हो गयी।

विपणन केन्द्र:-

विपणन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है तथा उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। विपणन के अर्न्तगत सभी के क्रियाकलाप जैसे- संग्रहण, संसाधन, भण्डारण एवं परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। जिनके द्वारा खाद्य पदार्थों को उपभोक्ता तक पहुँचाया जाता है। कृषि में विपणन का विशेष महत्व होता है। बिजनौर जनपद में वर्ष 1995 से 2015 के मध्य विपणन केन्द्रों को तालिका संख्या 4 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या 1: बिजनौर जनपद की विपणन केन्द्रों (वर्ष 1995–2015)

विपणन केन्द्रों	1995	2005	2015
बीज केन्द्र	0	387	463
उर्वरक केन्द्र	0	654	589
कीटनाशक केन्द्र	0	288	454
कृषि सेवा केन्द्र	9	17	23
ग्रामीण गोदाम	0	225	225
शीत भण्डार	14	14	7

स्रोत:– जिला सांख्यिकीय पत्रिका (वर्ष 1995, 2005 तथा 2015), अर्थ एवं संख्या विभाग, बिजनौर।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 1995 में बिजनौर जनपद के अर्न्तगत बीज केन्द्र, उर्वरक केन्द्र, कीटनाशक केन्द्र, ग्रामीण गोदाम की संख्या शून्य थी जो वर्ष 2005 में बढ़कर 387, 654, 288 तथा 225 हो गयी। वर्ष 2015 में बीज केन्द्र की संख्या बढ़कर 463, कीटनाशक केन्द्र 454 तथा उर्वरक केन्द्रों की संख्या घटकर 589 हो गयी। परन्तु वर्ष 2015 में जनपद में ग्रामीण गोदाम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार वर्ष 1995 में अध्ययन क्षेत्र में कृषि सेवा केन्द्र तथा शीत भण्डार की संख्या 9 एवं 14 थी। वर्ष 2005 तथा 2015 में कृषि सेवा केन्द्र की संख्या में वृद्धि हुई और यह बढ़कर 17 तथा 23 हो गयी। वर्ष 2005 में शीत भण्डार की संख्या 14 ही रही परन्तु वर्ष 2015 में यह संख्या घटकर 7 हो गयी।

निष्कर्ष:–

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र में अवस्थापनात्मक तत्वों में निरन्तर परिवर्तन परिलक्षित होता है। जिससे जनपद की सामाजिक–आर्थिक विकास की प्रक्रिया प्रभावित होती है। अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक–आर्थिक अवस्थापनात्मक तत्वों के अन्तर्गत शिक्षण संस्थाएँ, परिवहन सेवाएँ, वित्तीय संस्थाएँ एवं विपणन केन्द्रों का अध्ययन किया गया है। वर्ष 1995 की तुलना में बिजनौर जनपद में शिक्षण संस्थाएँ, परिवहन सेवाएँ, वित्तीय संस्थाएँ एवं विपणन केन्द्रों की संख्या में वर्ष 2015 में वृद्धि देखने मिलती है। औद्योगिक विकास हेतु अवस्थापनात्मक तत्वों का समुचित विस्तार अति आवश्यक है। अवस्थापनात्मक तत्वों की दृष्टि से बिजनौर जनपद एक उन्नत क्षेत्र है।

सन्दर्भ

1. बिजनौर जनपद सांख्यिकीय पत्रिका– 1995, 2000, 2005, 2010, 2015
2. गजेटियर ऑफ बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, 1981
3. गजेटियर ऑफ मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट, 1981
4. सिंह, महेन्द्र बहादुर तथा दूबे, कमला कान्त: प्रादेशिक विकास नियोजन, तारा बुक एजेन्सी, 2015, वाराणसी, पृष्ठ सं०–301
5. वाजपेयी, जितेन्द्र कुमार: शाहजहा; पुर जनपद में भूमि उपयोग का परिवर्तित स्वरूप एवं नियोजन–एक भौगोलिक अध्ययन, शोध प्रबन्ध, 2014, रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, पृष्ठ सं०–198 से 221।